उत्तर प्रदेश

ई-संदेश

6 जून, 2018 • वर्ष 1, अंक 20

सात दिन – सात पृष्ठ

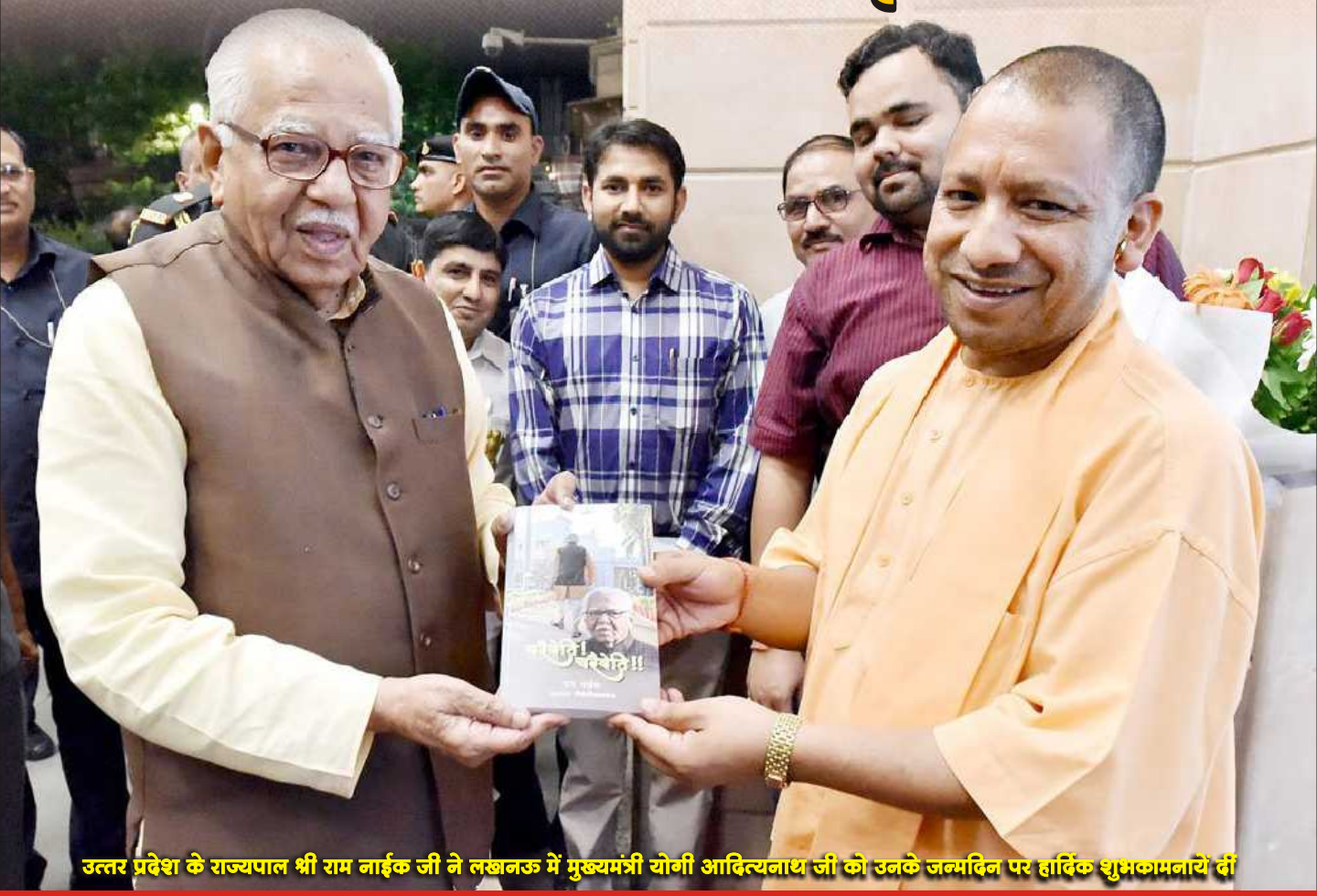

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनायें दीं

- नई दुग्ध नीति से पांच साल में 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
- बिजली चोरी रोकने के लिए खुलेंगे 75 नए थाने
- 2 अक्टूबर तक पूरा प्रदेश होगा ओडीएफ
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खातों में 308.4 करोड़ रूपये अंतरित
- भयमुक्त समाज सरकार की प्राथमिकता
- हरदोई में मुख्यमंत्री जी का ग्राम प्रधानों से सीधा संवाद

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

नई दुग्ध नीति से पांच साल में 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार ने दुग्ध नीति 2018 के अन्तर्गत पूंजी निवेश पर अनुदान, ब्याज में छूट और मानव संसाधन कें विकास हेतु प्रोत्साहन देने के विशेष प्रबंध किए हैं। सरकार के इस निर्णय से पशुपालकों को लाभ मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में पांच वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। सरकारी तथा निजी क्षेत्र की भागदारी के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण क्षमता और सह उत्पादों की रेंज में बढ़ोत्तरी होगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

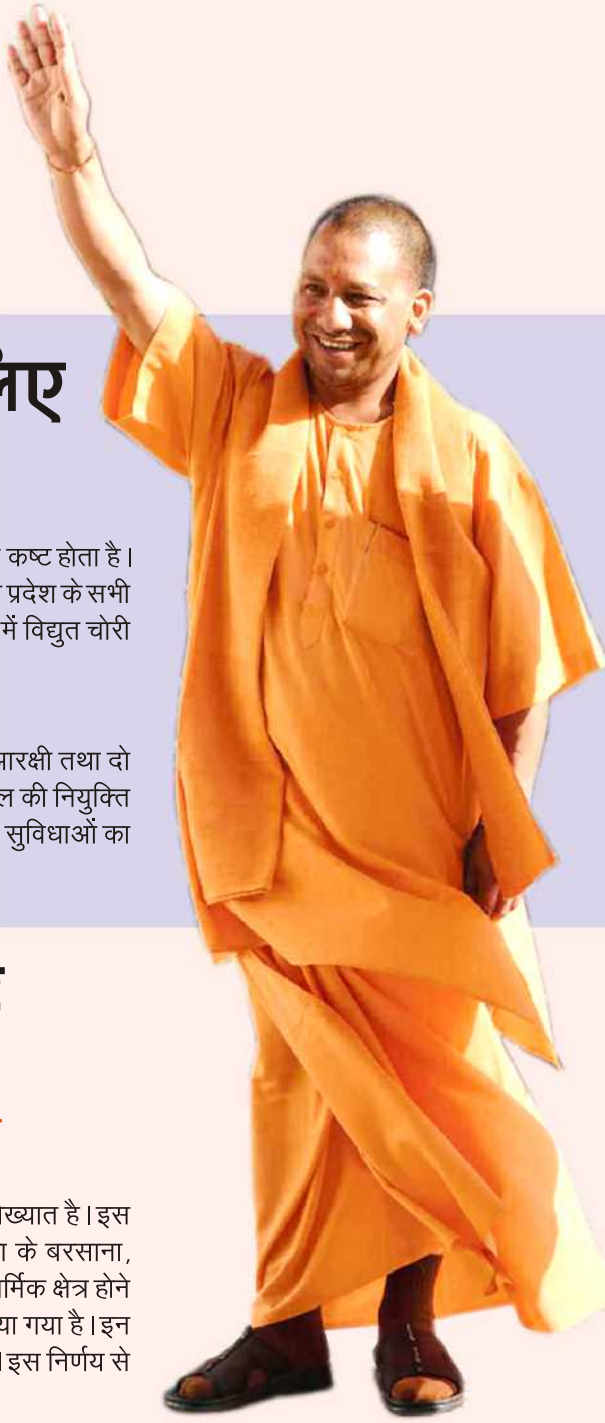

बिजली चोरी रोकने के लिए खुलेंगे 75 नए थाने

बिजली चोरी के कारण सुचारू विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है और आमजन को कष्ट होता है। अत: प्रदेश सरकार ने ईमानदार विद्युत उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक–एक एंटी पावर थेफ्ट थाना खोलने का निर्णय लिया है। थानों में विद्युत चोरी संबंधी मुकदमा दर्ज कराने से लेकर तकनीकी विवेचना में भी सुविधा होगी।

हर थाने में होंगे 28 पुलिसकर्मी

प्रत्येक थाने में एक प्रभारी निरीक्षक, पांच उपनिरीक्षक, 11 मुख्य आरक्षी, नौ आरक्षी तथा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित कुल 28 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। थानों में पुलिस बल की नियुक्ति हेतु सरकार ने 2157 पदों का सृजन किया है। पुलिसकर्मियों के वेतन एवं अन्य सुविधाओं का पूरा व्यय यूपी पावर कारपोरेशन द्वारा वहन किया जायेगा।

मथुरा के तीर्थ स्थलों पर नहीं बिकेगी शराब

बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव तथा राधाकुण्ड क्षेत्र में नहीं बिकेगी शराब

भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा एक पवित्र धर्मिक स्थल के रूप में विश्वविख्यात है। इस स्थल के धर्मिक महत्व के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि मथुरा के बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव तथा राधाकुण्ड क्षेत्र में शराब नहीं बिकेगी। धार्मिक क्षेत्र होने के कारण इन सभी क्षत्रों में पूरी तरह से शराबबंदी को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन क्षेत्रों में स्थापित शराब की दुकानों को दूसरे क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जायेगा। इस निर्णय से सरकारी कोष को 11.10 करोड़ रूपये की राजस्व हानि होगी।

कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार

प्रदेश के युवाओं के विस्तृत कौशल विकास की आवश्यकता है। उद्यमों का ट्रेन्ड देखते हुए शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ डिज़ाइन किए जाएंगे और समय के साथ उन्हें अपग्रेड भी किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर युवाओं के कौशल विकास करने से उन्हें उनके क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध कराने की सम्भावनाएं बढ़ जाएंगी और उन्हें अपना घर छोड़कर रोजगार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह विचार कौशल विकास के सम्बन्ध में दिए गए प्रस्तुतिकरण के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 821 विकास खण्ड हैं। इन विकास खण्डों में युवाओं के कौशल विकास की प्रभावी कार्ययोजना बनानी होगी। इस कार्य में एशियन डेवलपमेण्ट बैंक की मदद ली जाएगी।

स्थानीय आवश्यकता के अनुसार निर्धारित होगा कौशल विकास पाठ्यक्रम

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई 'एक जनपद–एक उत्पाद' योजना को ध्यान में रखते हुए भी कौशल विकास किया जाएगा। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए युवाओं का कौशल विकास सुनिश्चित किया जाएगा। सम्पूर्ण प्रदेश में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास के पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जाएगा।

युवाओं को रोजगार के उपयुक्त बनाने पर जोर

प्रदेश के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण आईटीआई तथा उ.प्र. कौशल विकास मिशन के तहत दिया जाता है। युवाओं को रोजगार के लिए उपयुक्त बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए कौशल विकास के साथ–साथ उनका हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं का कार्यकारी ज्ञान भी आवश्यक है। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ओ.डी.ओ.पी. योजना के तहत हस्तशिल्पियों के कौशल विकास प्रशिक्षण से उनके रोजगार की सम्भावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। इसके माध्यम से नये रोजगार सृजन और उद्यमों के स्थापन/वित्त पोषण का कार्य मुद्रा योजना, स्टार्ट–अप इण्डिया, स्टैण्ड–अप इण्डिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, एमएसएमई क्लस्टर योजना के माध्यम से कराया जाएगा। इसके तहत चिन्हित उत्पादों के विकास हेतु नई योजनाओं को तैयार कर लागू करवाया जाएगा।

भयमुक्त समाज सरकार की प्राथमिकता

भयमुक्त समाज की स्थापना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और कानून के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद भदोही की कानून–व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कानून–व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने भू–माफिया, पशु तस्करों तथा गम्भीर अपराधों में लिप्त अपराधियों पर कार्यवाही किए जाने के सख्त निर्देश देते हुए महिलाओं एवं अनुसूचित जाति–जनजाति के व्यक्तियों की सुरक्षा किए जाने तथा थाना स्तर पर एण्टी रोमियो टीम बनाने के निर्देश दिये।

कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ऑनलाइन एफ.आई.आर., 1090 'विमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन तथा डायल–100 के विषय में आम जनमानस को जानकारी दी जायेगी। भू–माफियाओं से मुक्त करायी गयी भूमि की सुरक्षा एवं उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित कराया जायेगा। जेल में बंद माफियाओं द्वारा जेल से अपराध न संचालित न होने पाये, इसके लिए समय–समय पर जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। सम्पूर्ण समाधान दिवस एवं थाना दिवस को अधिक प्रभावी बनाया जायेगा ताकि जनता में पुलिस एवं प्रशासन की छवि बेहतर बने।

भदोही को विकास योजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद भदोही में 8660.66 लाख रुपये की 106 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण तथा शिलान्यास के अवसर पर कहा कि जनपद भदोही हस्तशिल्प के लिए विश्व विख्यात है। भदोही की कालीन दुनिया के अन्दर विशिष्ट स्थान रखती है। हुनर के साथ अपनी विरासत को संजोए हुए है। प्रदेश सरकार कालीन हुनर का पूरा सम्मान करती है। भदोही कालीन के उद्यमियों के लिए ब्राण्डिंग कारोबार हेतु सरकार पूर्ण रूप से सहयोग करेगी, जिससे यहां के बुनकरों के साथ ही कालीन निर्यातक भी लाभान्वित होंगे तथा स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा।

2 अक्टूबर तक पूरा प्रदेश होगा ओडीएफ

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राज्य को 02 अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौचमुक्त घोषित किए जाने हेतु संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जनपदों में शौचालयों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए शौचालय निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए।

शौचालय निर्माण के लक्ष्य को प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारियों को हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी जिलाधिकारी प्रतिदिन एक घण्टा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा करेंगे एवं अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे। खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए उत्तरदायी होंगें।

कम प्रगति वाले जनपदों के जिलाधिकारियों से सीधी बात

प्रदेश में शौचालय आच्छादन में कम प्रगति वाले जनपदों में सीतापुर, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, बलिया, मऊ, कुशीनगर, लखनऊ, रायबरेली, महराजगंज, फैजाबाद, बलरामपुर, बाराबंकी, इलाहाबाद, हरदोई, फतेहपुर, लमीखपुर खीरी, चन्दौली, अलीगढ़, सुलतानपुर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, देवरिया, सम्भल, महोबा शामिल हैं।

समीक्षा में मुख्यमंत्री जी ने इन जनपदों के जिलाधिकारियों से सीधी बातचीत करते हुए उन्हें इस कार्य में तेजी लाते हुए गुणवत्तापरक ढंग से समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिये।

शौचालय निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष जोर

शौचालय के निर्माण की गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाएगी। निर्मित शौचालयों का शत–प्रतिशत सत्यापन तथा जियो टैगिंग (फोटोग्राफ अपलोडिंग) सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, ओ.डी.एफ. ग्रामों का सत्यापन भी किया जाएगा।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक प्रशिक्षित स्वच्छाग्रही की तैनाती की जाएगी। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, स्वयंसेवी संगठनों व संस्थाओं, सहभागी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम से जोड़ते हुए जनसहभागिता के साथ निर्माण लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा।

स्वस्थ भारत की ओर एक सार्थक पहल

स्वच्छ भारत अभियान का सीधा सम्बन्ध स्वस्थ भारत अभियान से है। जे.ई./ए.ई.एस. प्रभावित 38 जनपदों में शौचालय निर्माण कार्य में विशेष ध्यान देते हुए तेजी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बीमारियां गंदगी व खुले में शौच करने से सीधे सम्बन्धित हैं। इसलिए प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में शौचालय निर्माण कार्य को युद्धस्तर पर संचालित कर रही है।

निजी आवासों पर स्थापित होंगे रूफटाप सोलर पावर प्लांट

उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का प्राविधान किया है। इस कार्य के लिए प्रथम किश्त हेतु 12.50 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 25 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। निजी अवसरों पर ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना से सौर ऊर्जा कार्यक्रमों को गति मिलेगी। ग्रिड संयोजन के कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री तथा उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के तहत किया जायेगा। कार्य स्थल पर इसके सम्बंध में मुख्य विवरण शिलापट्ट बोर्ड के रूप में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रदर्शित किया जायेगा।

प्रदेश की हर तहसील और ब्लॉक में स्थापित होंगे कौशल विकास केन्द्र

प्रदेश सरकार ने सिडबी के साथ बनाया एक हजार करोड़ रुपए का कॉर्पस फण्ड

20 लाख लोगों को कौशल विकास के माध्यम से मिलेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश की प्रतिभा को देश व दुनिया में स्थान मिल रहा है। देश में स्किल्ड लोगों की कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें मंच प्रदान करने की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को एक योजक मिला है, जिसने कौशल विकास को विस्तार देने का काम किया। उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा राज्य है, जहां अलग–अलग क्षेत्रों में परम्परागत उद्योग स्थापित हैं। इसीलिए प्रदेश की सभी तहसीलों और ब्लॉकों में कौशल विकास के केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं का कौशल विकास करके उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 'एक जनपद, एक उत्पाद' योजना को कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के साथ इण्टीग्रेट किया गया है। इसके माध्यम से आने वाले समय में 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया हो सकेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह विचार 'इण्डिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता' 2018 के समापन अवसर पर 12 विभिन्न राज्यों से आए सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण–पत्र वितरण के अवसर पर व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप वैश्विक दूरियां निरन्तर कम हो रही हैं। साथ ही, युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। पूरा विश्व अब एक बाजार की शक्ल ले चुका है। ऐसे में बाजार में बने रहने के लिए बहुत सी चुनौतियां हैं। इस दृष्टिकोण से स्वयं को किसी कौशल में पारंगत बनाना नौजवानों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण और उपयोगी है।

विकास ही देश और प्रदेश की तरक्की और खुशहाली का आधार हो सकता है। विकास ही किसानों, नौजवानों के लिए अवसर पैदा करेगा और महिलाओं की सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री जी ने इटावा में 655 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि राशन कार्ड, आवास, बिजली कनेक्शन, शौचालय, जन–धन, पेंशन आदि योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को जरूर मिलेगा। उन्होंने नौजवानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी भर्ती में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश के युवाओं के साथ भेदभाव करेगा, तो उसकी जगह सिर्फ जेल होगी।

प्रदेश की तरक्की तथा खुशहाली पर ध्यान

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार भी राज्य के व्यापक हित में लगातार कार्य कर रही है। इसके तहत सामान्यजन को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ ही, आपराधिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास एवं लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करना है। यह सब प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित व उज्ज्वल बनाने के लिए किया जा रहा है।

अन्तिम पयदान पर खड़े व्यक्ति को शासकीय योजनाओं का लाभ

सभी पात्र व्यक्तियों को 'आयुष्मान भारत' योजना का लाभ दिलाने के लिए कृत संकल्पित है सरकार

प्रदेश सरकार ने एक साल में ग्रामीण क्षेत्र में बनवाकर दिए 8 लाख 85 हजार आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खातों में 308.4 करोड़ अंतरित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (शहरी) के तहत प्रदेश के 75 जनपदों के 54,310 चयनित लाभार्थियों के खातों में 308.40 करोड़ रुपए की प्रथम किश्त की धनराशि पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से अंतरित की। अंतरित धनराशि की सूचना लाभार्थी को मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने लखनऊ के बख्शी का तालाब, इटौंजा, अमेठी और गोसाईगंज के लाभार्थियों को निर्मित आवास की प्रतीकात्मक चाभी प्रदान की।

प्रदेश की नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर निगमों के आवासहीन पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए व प्रदेश सरकार द्वारा 01 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए की कुल धनराशि तीन किश्तों में अवमुक्त की जाती है। जीरो लेवल पर प्रथम किश्त के रूप में 50 हजार रुपए, द्वितीय किश्त के रूप में लेण्टर स्तर पर 1.5 लाख रुपए तथा तीसरी व अंतिम किश्त के रूप में 50,000 रुपए आवास पूर्ण होने पर दिए जाते हैं।

वन नेशन-वन इलेक्शन की सिफारिश

2029 में लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव हों एक साथ

चुनाव खर्चों में कमी लाने और बार-बार चुनाव की प्रक्रिया के कारण विकास कार्यों में बाधा आने की समस्या के दृष्टिगत विधि आयोग के सुझाव पर 'वन नेशन वन इलेक्शन' हेतु प्रदेश में गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए लोकसभा और विधानसभ चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की।

समिति ने सुझाव दिया है कि राज्यों के चुनाव आगे-पीछे करके 2024 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकता है। वर्ष 2029 तक स्थानीय निकाय के चुनाव को जोड़ते हुए सभी चुनाव एक साथ कराया जाना संभव है। कुछ राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल में कटौती करके और कुछ का कार्यकाल आगे बढ़ाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

समिति की प्रमुख सिफारिशें

- सभी चुनावों के लिए एक मतदाता सूची
- यूनिक नंबर की तरह हों मतदाता पहचान पत्र
- सोलह वर्ष के युवाओं का हो डेटा बेस
- क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव न हो

ई–डिस्ट्रिक्ट से मिलेंगी सहज सुलभ सुविधाएं

प्रदेश सरकार जनमानस को किफायती, पारदर्शी एवं सहज–सुलभ रीति सेवाएं उपलबध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने जनहित गारण्टी से संबंधित सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आम जन सामान्य को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

जन सुविधाओं के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों का मूल अंक पत्र/प्रमाण–पत्र का वापस करना, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों के चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति, परीक्षा परिणाम आधारित अंक पत्र, सह–चरित्र प्रमाण–पत्र को जारी करना, उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण–पत्र को जारी करना, अन्तरण प्रमाण पत्र को जारी करना, अनुकृति अंक पत्र को जारी करना, अनुकृति प्रमाण–पत्र को जारी करना, पुनरीक्षित अंक पत्र को जारी करना, पुनरीक्षित प्रमाण–पत्र को जारी करना, स्कूटनी परिणाम को घोषित करना तथा काशनमनी को वापस करने की सुविधाएं आम जन मानस को उपलब्ध कराई जाएगी।

हरदोई में मुख्यमंत्री जी का ग्राम प्रधानों से सीधा संवाद

ग्राम प्रधान समाज की वह कड़ी हैं, जो अपने ग्राम की दशा व दिशा दोनों ही परिवर्तित कर सकते हैं। ग्राम प्रधानों को अपनी सकारात्मक सोच से भेदभाव रहित ग्राम के विकास में अपना योगदान देना होगा। ग्राम प्रधान जब चुनाव लड़ता है, तो वह, व्यक्ति विशेष अथवा परिवार विशेष का सदस्य होता है, परन्तु जब वह निर्वाचित होकर आता है, तो वह सर्वजन का सदस्य हो जाता है। इसलिए ग्राम प्रधान अपने गांव में 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा को आत्मसात करते हुए ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपने परिजन सा व्यवहार कर शासन की संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराएं। तभी गांव में खुशहाली एवं भाइचारे की भावना को बल मिलेगा और लोगों का जीवन सुखमय व जीवन स्तर ऊँचा उठेगा।

समाज व राष्ट्र निर्माण हेतु ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी

हरदोई में 'ग्राम स्वराज अभियान' के अन्तर्गत आयोजित 'मुख्यमंत्री ग्राम प्रधान संवाद' कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्राम प्रधानों का आह्वान करते हुए कहा कि वह अपनी ऊर्जा का प्रयोग समाज व राष्ट्र के निर्माण में करें। शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह हमारा नैतिक दायित्व ही नहीं अपितु परम कर्तव्य भी है।

जनता में जागरूकता लायेंगे ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान जनता में जनजागरूकता लाएंगे, ताकि वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और योजनाओं का लाभ उठा सकें। ग्राम पंचायतों की समितियां सक्रिय होकर जमीनी कार्य करेंगी। केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को बजट सीधे ग्राम निधि खाते में मुहैया कराया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार से उच्चाधिकारियों की दखलन्दाजी भी नहीं है। इसलिए ग्राम प्रधान जिस प्रकार भी चाहें, अपने ग्राम का विकास कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने गांव की स्वच्छता पर बल देते हुए कहा कि गांव को स्वच्छ रखने में ग्राम प्रधान अपनी महती भूमिका निभाएं, तभी गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना साकार हो सकेगी।

5 जून 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

51 बुनकरों को हर साल मिलेगा संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार

हथकरघा बुनकरों में प्रतिस्पर्धा पैदा कर उन्हें उत्तम गुणवत्तायुक्त वस्त्र बनाने हेतु प्ररित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना प्रारंभ करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये पुरस्कार परिक्षेत्र और राज्य स्तर के होंगे।

इतनी होगी पुरस्कार धनराशि

योजना के अन्तर्गत परिक्षेत्र स्तर पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के तौर पर क्रमशः 20, 15 और 10 हजार रूपये के पुरस्कार दिये जायेंगे। इसमें कुल 39 बुनकरों को सम्मानित किया जायेगा। राज्य स्तर पर पुरस्कार 12 बुनकरों को चार श्रेणियों में दिये जायेगे। इसमें प्रथम पुरस्कार एक लाख रूपये, द्वितीय 50 हजार और तृतीय 25 हजार रूपये का होगा।

कूड़े से बनेगी खाद और बिजली

प्रदेश में प्रतिदिन 15 हजार टन कूड़ा निकलता है। इस कूड़े–कचरे के प्रबंधन के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति (कूड़ा निस्तारण) लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में कूड़े से बिजली और खाद बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस नीति से प्रदेश के शहरों और कस्बों में स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए उच्च मानक स्थापित होगे और कूड़े के निस्तारण की चुनौती से निपटने में सहायता मिलेगी।

पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे पर सुल्तानपुर के पास बनेगी एयर स्ट्रिप, आपात स्थिति में उतरेंगे सैन्य विमान

प्रदेश में आधुनिक फार्मा पार्क, अनुसंधान व निर्माण का मार्ग प्रशस्त

फैजाबाद में राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी को मिले 29 लाख

शीरि की भण्डारण क्षमता में दस प्रतिशत की वृद्धि

92 प्रतिशत गेहूँ खरीद पूरी

अब तक 45.85 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद

912050 किसानों को किया गया 7936.31 करोड़ रूपये का भुगतान

मूल्य समर्थन योजना के तहत प्रदेश में खोले गए विभिन्न गेहूँ कय केन्द्रों के माध्यम से अब तक 45.85 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की जा चुकी है। पिछले साल इसी समयावधि में लगभग 30.07 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई थी। पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग डेढ़ गुना अधिक खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 9,12,050 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा किसानों को 7936.31 करोड़ रूपये का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जा चुका है। रबी क्रय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष लगभग 92 प्रतिशत खरीद की जा चुकी है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी